हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 145 लखनऊ, शुक्रवार 16 जनवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

योगी सरकार का 100 दिवसीय विशेष सघन टीबी रोगी खोज अभियान फरवरी से

जनभागीदारी के लिए सांसद से लेकर पार्षद तक को शामिल करने के दिये निर्देश
बुजर्गों, गंभीर रोगियों व मलिन बस्तियों में टीबी स्क्रीनिंग पर जोर
प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक चलेगा जागरूकता अभियान

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार एक बार फिर तपेदिक (टीबी) उन्मूलन के लिए प्रदेश में 100 दिवसीय विशेष सघन रोगी खोज अभियान शुरू करने जा रही है। फरवरी में शुरू हो रहे अभियान में जनप्रतिनिधियों व विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिकतम मरीजों को खोजकर उनका इलाज शुरू करने की रणनीति है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी अपर निदेशकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने टीबी रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास विभाग को लिखा है।

सघन खोज अभियान से टीबी से होने वाली मौतों में 17 फीसदी की कमी

स्वास्थ्य सचिव डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि सघन टीबी खोज अभियान 7 दिसंबर 2024 से चलाया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2015 के सापेक्ष प्रति एक लाख व्यक्तियों में मरीजों की संख्या में 17 प्रतिशत और टीबी के कारण होने वाली मृत्यु में भी 17 फीसदी की कमी आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभाग ने एक बार फिर से फरवरी में सघन टीबी रोगी खोज अभियान चलाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य महानिदेशक (डीजी) डॉ. आरपी सिंह सुमन ने जनभागीदारी के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता से बच्चों को किया जाएगा जागरूक

सभी सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि दो माह में सांसदों के साथ जनपद स्तरीय समीक्षा करवाएं और उन्हें निःक्षय शिविर व अन्य जनभागीदारी गतिविधियों में शामिल करें। ये समीक्षा बैठकें आगे भी जारी रहेंगी। इसके अलावा विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, प्रधानों व पार्षदों को भी अभियान से जोड़ें। अभियान में सामाजिक जन जागरूकता बढ़ाने के लिए श्माई भारतश वालंटियर्स व अन्य पंजीकृत निःक्षय मित्रों का भी उपयोग करें। डीजी ने सभी कारागारों व मलिन बस्तियों में टीबी स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता समेत विभिन्न माध्यमों से छात्र–छात्राओं में जागरूकता फैलाने के लिए कहा है। इसके अलावा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि वे टीबी के लक्षण वाले लोगों को स्क्रीनिंग के लिए भेज सकें। परिवहन विभाग से जुड़े समस्त चालकों व कंडक्टरों की स्क्रीनिंग कराने व कारखानों में काम करने वालों की भी शिविर लगाकर जांच करने को कहा गया है। यह है अभियान की रणनीति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व उससे नीचे की स्वास्थ्य इकाइयों से पांच प्रतिशत और जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों से 10 प्रतिशत लोगों को सामान्य ओपीडी से टीबी जांच के लिए रेफर करना। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से टीबी जांच के लिए सैम्पल ट्रांसपोर्टरों की व्यवस्था कराना। बुजुर्गों व गंभीर मरीजों की यथासंभव जांच कराना। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट, विभागों, संस्थानों को निःक्षय मित्र के रूप में प्रेरित करना।

दिल्ली में 28वें सीएसपीओसी में बोले पीएम मोदी, भारत ने बनाया विविधता को लोकतंत्र की शक्ति

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत बनाया है और दुनिया को दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं उसके विकास को स्थिरता, स्केल और गति प्रदान करते हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बहस, संवाद और मिलकर फैसला

लेने की लंबी परंपरा रही है। उन्होंने कहा, ''भारत में, लोकतंत्र का मतलब है अंतिम पायदान तक सेवाओं की पहुंच।'' उन्होंने यह भी कहा कि भारत हर वैश्विक मंच पर 'ग्लोबल साउथ' की चिंताओं को मजबूती से उठा रहा है। मोदी ने कहा, ''अपनी ळ20 की अध्यक्षता के दौरान भी, भारत ने 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं को वैश्विक एजेंडा के केंद्र में रखा था।'' संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में 14 से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में करीब 60 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसमें आज के कई संसदीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिनमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाकर रखने में अध्यक्ष (स्पीकर) और पीठासीन अधिकारी की भूमिका भी शामिल है। संसदीय कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल, संसद सदस्यों पर सोशल मीडिया का असर, संसद के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए नई रणनीति और मतदान के अलावा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने आदि पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है।

ईरान में फसें जम्मू कश्मीर के छात्र, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र से की मांग, भारतीय छात्रों की हो सुरक्षित वापसी

एजेंसी

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईरान में मौजूदा तनावपूर्ण हालातों के बीच वहां फंसे कश्मीरी छात्रों समेत सभी भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की बृहस्पतिवार को मांग की। मुफ्ती ने यह मांग उन कश्मीरी छात्रों के अभिभावकों की अपील के एक दिन बाद की है, जिन्होंने ईरान में पढ़ रहे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई थी और केंद्र सरकार से अपने बच्चों की सकुशल वापसी के लिए अपील की थी। मुफ्ती ने सोशल मीडिया मंच श्एक्सश पर लिखा, ''ईरान की अस्थिर स्थिति के बीच कश्मीर समेत देशभर के हजारों छात्र वहां फंसे हुए हैं। इसने उन माता–पिता के मन में गहरा डर पैदा कर दिया है, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। मैं विदेश मंत्री एस. जयशंकर और विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप कर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का

आग्रह करती हूं। एक अनुमान के मुताबिक, छात्रों समेत लगभग 10,000 से अधिक भारतीय वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नया परामर्श जारी कर छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों समेत सभी भारतीयों से व्यावसायिक उड़ानों या अन्य साधनों के जरिए ईरान छोड़ने का आग्रह किया है। ईरान में यह संकट पिछले महीने तब शुरू हुआ जब वहां की मुद्रा रियाल रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई। तेहरान से शुरू हुआ यह विरोध ा प्रदर्शन अब सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में वहां की स्थिति काफी बिगड़ी है और देशव्यापी प्रदर्शनों में अब तक 2,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर ममता बनर्जी, बंगाल सरकार और डीजीपी को नोटिस भेजा

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस आरोप को बृहस्पतिवार को ''बेहद गंभीर'' बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसकी जांच में ''बाधा पैदा की''। न्यायालय ने इस बात की समीक्षा करने पर सहमति जताई कि क्या किसी राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां घ्किसी गंभीर अपराध के मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप कर सकती हैं। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है जिन्होंने आठ जनवरी को 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आई–पैक) कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा था। उसने राज्य पुलिस को छापेमारी की कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने मुख्यमंत्री बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को

ईडी की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिनमें आई–पैक परिसर में छापेमारी में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा, ''हमें लगता है कि देश में कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने और प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने के लिए इस मुद्दे की समीक्षा करना आवश्यक है ताकि अपराधियों को किसी विशेष राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की छत्रछाया में संरक्षण न मिल सके।' उसने कहा, ''इसमें बड़े सवाल शामिल हैं और उठाए गए हैं, जिन्हें अगर अनसुलझा छोड़ दिया जाए तो स्थिति और बिगड़ जाएगी तथा अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग संगठनों के शासन को देखते हुए किसी न किसी राज्य में अराजकता की स्थिति बनी रहेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के चुनावी काम में हस्तक्षेप करने की शक्ति किसी केंद्रीय एजेंसी के पास नहीं है लेकिन साथ ही यदि केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए सद्भावना से काम कर रही हैं, तो सवाल उठता है कि क्या दलगत गतिविधि ा की आड़ में एजेंसियों को अपने कर्तव्य निभाने से रोका जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख तय की गई है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडी की छापेमारी संबंध ी मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय में हुए हंगामे से वह अत्यंत व्यथित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी आई–पैक से जुड़े स्थानों पर ईडी की छापेमारी और जब्ती कार्रवाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई अदालत कक्ष के भीतर ''अनियंत्रित अराजकता'' का हवाला देते हुए 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। ईडी ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि जांच एजेंसी की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ''दखलअंदाजी और बाध ा'' एक बेहद चौंकाने वाले चलन को दर्शाती हैं। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि पहले भी वैधानिक प्राधिकरणों ने वैधानिक शक्ति का जब–जब प्रयोग किया। बनर्जी वहां पहुंचीं और उन्होंने दखलअंदाजी की। मेहता ने कहा, ''यह एक बेहद चौंकाने वाले चलन को दर्शाता है।'' उन्होंने कहा कि इससे इस प्रकार के कृत्यों को और बढ़ावा मिलेगा तथा केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ''राज्यों को लगेगा कि वे दखल दे सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और फिर धरने पर बैठ सकते हैं।

माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान पर्व पर उठी आस्था की लहर, 1 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई पुण्य की डुबकी

साफ मौसम से त्रिवेणी में दो दिनों में स्नान करने वालों की संख्या 2 करोड़ के पास पहुंची
साधु-संतों और कल्पवासियों के साथ किन्नर अखाड़े ने भी किया भव्य स्नान, हर-हर महादेव की हर तरफ गूंज
मेला क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर रही चौकसी, सक्रिय और सतर्क प्रशासनिक मशीनरी से स्नान पर्व सकुशल संपन्न

बीएनई

प्रयागराज। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ा। त्रिवेणी तट पर आयोजित माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व पर देश के कोने–कोने से आए श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। प्रशासन की तरफ से की गई चाक चौबंद व्यवस्था के चलते माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व सकुशल संपन्न हो गया। माघ मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया। कल्पवासियों ने त्रिवेणी तट पहुंच कर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और खिचड़ी, गुड़ का दान कर संक्रांति की परम्परा को पूरा किया। दंडी साधुओं और आचार्य सम्प्रदाय के संतों ने नजदीकी गंगा घाटों पर डुबकी लगाई और उत्तरायण भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। माघ मेले में अखाड़ों के स्नान की परम्परा नहीं है, लेकिन अखाड़ों से जुड़े कई नागा संन्यासी भी संक्रांति स्नान के लिए संगम पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से मोक्ष की डुबकी लगाई। इसी दौरान ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गंगा पूजन कर अपनी श्गो प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्राश का विधिवत शुभारंभ किया। मौसम खुला होने की वजह से त्रिवेणी में संक्रांति स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई। मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि मकर संक्रांति पर बृहस्पतिवार शाम 4 बजे तक 91 लाख से अधिक लोग पुण्य की डुबकी लगा चुके थे और सूर्यास्त तक त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1.03 करोड़ पहुंच गई। सनातनी किन्नर अखाड़े ने किया गंगा स्नान, बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर संकल्प का आवाहन मकर संक्रांति स्नान पर्व पर सभी समान भाव से पुण्य की डुबकी लगाते दिखाई

दिए। माघ मेला क्षेत्र में प्रयागवाल नगर में कल्पवास कर रहा सनातनी किन्नर अखाड़ा पूरे उत्साह के साथ सुबह गंगा तट के लिए निकला। इस दौरान रास्ते में किन्नर अखाड़े के शिष्यों द्वारा तांडव नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय व अलौकिक बना दिया। अखाड़े के सदस्यों ने गंगा तट पहुंचकर सबसे पहले अपनी कुलदेवी बउचरा माता को गंगा स्नान कराया और फिर सामूहिक स्नान किया। इस दौरान अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसे देखते यूपी के सीएम योगी जी के सभी सनातनियों के एकजुट होने के आह्वान को संकल्प में बदलने का समय आ गया है। सभी सनातनी एकजुट होंगे तभी सुरक्षित रहेंगे।

मायावती ने जन्मदिन पर कार्यकताओं को दिया बड़ा संदेश

कहा– चुनाव में इस शर्त पर होगा गठबंधन पर विचार

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 सहित देश में होने वाले सभी छोटे–बड़े चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में अपना 70वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट किया, ''हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी चुनाव अकेले लड़ना अधिक उचित समझा है। किसी भी पार्टी के साथ किसी भी चुनाव में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि यह भरोसा हो जाता है कि किसी गठबंधन सहयोगी पार्टी के खासकर अगड़ी जातियों के वोट बसपा को स्थानांतरित हो सकते हैं, तभी गठबंधन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वर्षों लग सकते हैं। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बसपा के चार कार्यकालों को याद करते हुए एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि इसे साकार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह जुट गए हैं, ताकि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य जातिवादी पार्टियां विभिन्न हथकंडे अपना रही हैं जिनका मुंहतोड़ जवाब देकर उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनानी है। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी ईवीएम में धांधली और बेईमानी हो सकती है, इसके बावजूद बसपा पूरे देश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव

लड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों का मानना है कि ईवीएम में धांधली करने वालों का सिस्टम कभी भी विफल हो सकता है और तब सही चुनाव परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में ईवीएम का विरोध बढ़ रहा है। बसपा प्रमुख ने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा के संस्थापक कांशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया और उनकी उपेक्षा की गई थी। उन्होंने कहा कि अन्य जातियों के साथ–साथ मुस्लिम समाज के साथ भी अन्याय हुआ है। मायावती ने दावा किया कि बसपा सरकार के दौरान दंगे नहीं हुए और यादव समाज का भी पूरा ध्यान रखा गया। इससे पहले मायावती के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्सश पर लिखा, ''बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्रीराम से आपके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।'' समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, ''आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उन्हें स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं।'' उन्होंने आगे लिखा, ''शोषित, वंचित, उत्पीड़ित और उपेक्षित समाज के मान–सम्मान एवं अधिकारों के लिए उनका संघर्ष निरंतर बना रहे।

संक्षिप्त समाचार

दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल की सजा, अदालत ने लगाया 29 हजार रुपये का जुर्माना

एजेंसी

बलिया। उत्तर प्रदेश में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 13–वर्षीय एक किशोर के साथ दुष्कर्म एवं मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के दो वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को बुधवार को दोषी करार दिया और 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बलिया जनपद स्थित सहतवार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोर 12 अक्टूबर 2023 की शाम को अपने घर के सामने खेल रहा था कि अजय पासवान नामक व्यक्ति उसे निर्जन स्थान पर ले गया तथा उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। अभियोग के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग से मारपीट भी की तथा जान से मारने की उसे धमकी दी। इस मामले में किशोर के पिता की तहरीर पर घटना के अगले दिन अजय पासवान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल किया।

संपादकीय

गिग–वर्कर की सुध

गिग वर्कर्स की हड़ताल और उनके मुश्किल हालात को लेकर समाज में बढ़ती फिक्र के बाद हुए सरकारी हस्तक्षेप से गिग वर्कर्स की बड़ी मुश्किल हल हुई है। कोहरे–ठंड और बेतरतीब ट्रैफिक के बीच गिग–वर्कर्स पर दस मिनट में सामान उपभोक्ता तक पहुंचाने का दबाव एक बड़े तनाव की वजह बना हुआ था। गिग–वर्कर्स को हीमैन मानकर द्रुत गति से वाहन दौड़ाकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। कुछ डिलीवरी ब्वॉयज के दुर्घटनाग्रस्त होकर जान गंवाने व घायल होने के भी समाचार थे। अब यह सुखद ही है कि केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनियां कष्टदायक दस मिनट में डिलीवरी की व्यवस्था खत्म करने को तैयार हो गई हैं। इटर्नल के स्वामित्व वाली इकाई ब्लिंकिट, जिसने दस मिनट में डिलीवरी को अपने कारोबार की आक्रामक विज्ञापन रणनीति का हथियार बना लिया था, ने अब अपने मंचों से दस मिनट में डिलीवरी का दावा हटा लिया है। निश्चित रूप से यह अमानवीय ही था कि बेकारी का त्रास झेलते युवाओं पर आनन–फानन दस मिनट में सामान उपभोक्ता तक पहुंचाने का दबाव बनाया जाए। लंबी ड्यूटी, कम पैसा और जल्दी सामान पहुंचाने के दबाव में बड़ी संख्या में गिग–वर्कर्स काम छोड़ जाते थे। आजकल ठंड के मौसम में उपभोक्ता घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। अतरू उत्तर भारत में भीषण सर्दी और कोहरे के बीच दस मिनट में तेजी से सामान पहुंचाना दुष्कर कार्य था। भारत में आम ट्रैफिक की जटिल स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सड़क हादसों के कारण उनका जीवन जोखिम में बना रहता था। इतना ही नहीं, कई बार डिलीवरी ब्वॉयज को बहुमंजिला इमारतों और कालोनियों के सुरक्षा गार्डों से जूझना पड़ता था, जिससे उन्हें सामान पहुंचाने में देरी हो जाती थी। फिर उपभोक्ता के मोबाइल पर मिले ओटीपी के बाद उनका सामान डिलीवर माना जाता था। समय पर सामान की डिलीवरी न होने पर उनके कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन कमतर आंका जाता है। दरअसल, गिग वर्कर्स को अच्छी रैंक तभी मिलती है जब वे दस मिनट में सामान पहुंचा देते हैं, जिसके चलते वे मानसिक तनाव में रहते थे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों दस मिनट में डिलीवरी का दबाव झेलते तथा मेहनताने में कमी आदि मांगों को लेकर गिग–वर्कर्स ने देशव्यापी हड़ताल की थी। हालांकि, कंपनी मालिकों ने साल के आखिरी दिनों में उत्सव के माहौल में डिलीवरी बाधित होते देख हड़ताल को कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन इस हड़ताल से पूरे देश का ध्यान गिग–वर्कर्स की जायज मांगों की तरफ गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कई राजनेताओं ने भी गिग–वर्कर्स के मुद्दे को जोर–शोर से उठाया। पिछले दिनों ध्यान आकर्षण के लिए बाकायदा राघव चड्ढा डिलीवरी ब्वॉय की ड्रेस पहनकर सामान डिलीवर करने भी गए। निस्संदेह, डिलीवरी ब्वॉयज का काम बेहद चुनौतीपूर्ण है, काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं और उसके अनुपात में मेहनताना बेहद कम है। इन्हीं चिंताओं के बाद केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया लेबर कोड चर्चा में आया, जिसमें उल्लेख है कि गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नियोक्ता कंपनी द्वारा दी जाएं। यह विडंबना ही है कि गिग वर्कर्स की मेहनत से क्विक कॉमर्स कंपनियों का कारोबार तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन गिग वर्कर्स की माली हालत नहीं सुधरी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स थोड़े समय काम करके नौकरी छोड़ देते हैं। निर्विवाद रूप से आज जरूरी है कि गिग वर्कर्स ही नहीं, तमाम असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अविलंब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। उन्हें बीमा, न्यायोचित काम के घंटे, समय पर समुचित भुगतान व चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस दिशा में कानून बनाना ही काफी नहीं होगा, जरूरत लगातार इस बात की निगरानी की भी होगी कि धरातल पर इन कानूनों का कितना अमल हो रहा है। निश्चित रूप से असंगठित क्षेत्र के हर कामगार की सुध ली जानी चाहिए। तभी देश में श्रम की गरिमा स्थापित हो सकेगी। यही देश की युवा श्रमशक्ति का भी सम्मान होगा।

राशिफल

मेष :– पुराने गलतियो से सीख लेते हुए वर्तमान को सुधारें। अच्छे कायरे से परिजनो के दिल में जगह बनावें। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न करें।

बृषभ :– भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ति में असमर्थता जैसी पूर्वाग्रह मन में निराशा पैदा करेगी। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी।

मिथुन :– मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरे में न गंवायें। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ संभव। संवेदनशील शरीर ग्रहो की प्रतिकूलता से बिमार पड़ सकता है।

कर्क :– सब कुछ सामान्यतः ठीक होते हुए भी मन में अरुचितकर लगेगा। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट होगा। पिता के स्वास्य के प्रति सचेत रहें।

सिंह :– किसी की अस्वस्थता से परिवार में कष्ट का वातावरण रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यवश घर से दूर जाना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कायरे के प्रति आलस्य न करें, नुकशान हो सकता है।

कन्या :– प्रतिभाओं के बावजूद भी हीन भाव उन प्रतिभाओं के लाभ से वन्चित हो सकता है। कल्पनाओं में जीना छोड़ कर भौतिक जगत के अनुरूप चलने का प्रयास करें।

तुला :– योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। मस्त–मौला मन मौज मस्ती समय व्यर्थ कर महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाह होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में परिश्रम तिब्र होगा।

वृश्चिक :– नये घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन अत्यंत प्रसन्न होगा। नये कायरे के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न शील बनें।

धनु :– नए क्षेत्रों मे प्रयास से लाभ संभव है। समस्याओ के समाधान से उत्साह में बृद्धि होगी। नए सम्बन्धों के सहयोग से आर्थिक कठिनाईयां दूर होंगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव।

मकर :– सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ति में असमर्थता जैसी पूर्वाग्रह मन में निराशा पैदा करेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव पहुंच सकता है।

कुंभ :– किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिया गया निर्णय से पश्चाताप का कारण बन सकता है। नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी।

मीन :– मन को सकारात्मक दिशा प्रदान करें। भाग्य से प्राप्त अच्छे–बुरे सभी परीस्थितियों के साथ समझौतावादी बनें। अपने सुख–दुख को छोड़ परिजनों के सुख के बारे में सोचें।

शिक्षा और सुरक्षा के बीच फँसी छात्राएँ : यौन शोषण के अड्डे बनते स्कूल-कॉलेज

– डॉ. प्रियंका सौरभ

शिक्षा को भारतीय समाज में 'मंदिर' कहा जाता रहा हैकृएक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ ज्ञान, संस्कार और भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से शिक्षण संस्थानों से यौन उत्पीड़न, मानसिक शोषण, डर और असुरक्षा की खबरें सामने आ रही हैं, उसने इस धारणा को गहरी चोट पहुँचाई है। सवाल यह नहीं है कि घटनाएँ हो रही हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय वास्तव में छात्राओं के लिए सुरक्षित हैं? हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों में शिक्षा संस्थानों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समस्या किसी एक संस्थान या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। प्रोफेसरों पर आरोप, प्रबंधन की भूमिका, शिकायतों को दबाने की प्रवृत्ति और पीड़िताओं को चुप कराने का सामाजिक दबावकृये सब मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं, जहाँ अपराध से ज्यादा खतरनाक हो जाता है उसका छिपाया जाना।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अधिकांश मामलों में पीड़ित सामने आने से डरती हैं। डरकृकरियर के खत्म हो जाने का, बदनामी का, संस्थान से निकाले जाने का और समाज द्वारा दोषी ठहरा दिए जाने का। यही डर अपराधियों को ताकत देता है और व्यवस्था को मौन रहने का बहाना। जब शिकायत करना ही जोखिम बन जाए, तब कानून की मौजूदगी भी बेमानी लगने लगती है। कानून अपने स्तर पर मौजूद है। यौन उत्पीड़न से जुड़े नियम, आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी), विशाखा दिशानिर्देश और पोश अधिनियमकृसब कुछ कागजों में है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई संस्थानों में ये समितियाँ या तो नाममात्र की हैं या फिर प्रबंधन के प्रभाव में काम करती हैं। शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने के बजाय मामले को "संस्था की छवि" के नाम पर दबाने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि न्याय की प्रक्रिया पीड़िता के लिए एक और मानसिक उत्पीड़न बन जाती है। शिक्षण संस्थानों में सत्ता का असंतुलन भी इस समस्या की जड़ में है। शिक्षक, प्रबंधन और प्रशासन के पास मूल्यांकन, नियुक्ति, प्रमोशन और भविष्य तय करने की शक्ति होती है। इस शक्ति का दुरुपयोग जब व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए किया जाता है, तो छात्रा या जूनियर स्टाफ खुद को असहाय महसूस करता है। यही असहायता अपराध को जन्म देती है और अपराधी को संरक्षण। एक और गंभीर मुद्दा हैकृसंवेदनशीलता की कमी। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम और डिग्री तक सीमित हो गई है। नैतिकता, लैंगिक सम्मान और मानवीय मूल्यों की बात भाषणों तक सिमट गई है। जब शिक्षक ही मर्यादा लांघते दिखाई दें, तो छात्रों को समाज से क्या संदेश जाता है? ऐसे में "शिक्षा का मंदिर" कहना एक विडंबना बनकर रह जाता है। राज्य सरकारों और शिक्षा विभागों की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती कि वे आदेश जारी कर दें या हेल्पलाइन नंबर छपवा दें। ज़रूरत है प्रभावी निगरानी की, नियमित ऑडिट की और स्वतंत्र शिकायत तंत्र की। शिकायत समिति में बाहरी, निष्पक्ष और महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। शिकायत की गोपनीयता और पीड़िता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होकृयह केवल नियम नहीं, व्यवहार में दिखना चाहिए। समाज की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक हम पीड़िता से सवाल पूछते रहेंगेकृ"वहाँ क्यों गई?", "पहले क्यों नहीं बताया?"कृतब तक अपराधी बेखौफ रहेगा। दोषी कौन है, यह तय करने की जिम्मेदारी कानून की है, लेकिन सहानुभूति और समर्थन समाज को देना होगा। चुप्पी तटस्थता नहीं, बल्कि अपराध के पक्ष में खड़ा होना है। आज आवश्यकता है भरोसे कीकृ ऐसे भरोसे की, जिसमें छात्रा निडर होकर शिकायत कर सके; शिक्षक अपने आचरण के प्रति जवाबदेह हों; और संस्थान अपनी छवि से ज्यादा अपने छात्रों की सुरक्षा को महत्व दें। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि सुरक्षित और संवेदनशील नागरिक तैयार करना भी है। यदि सच में हमें शिक्षा को मंदिर बनाए रखना है, तो पहले उसे डर, शोषण और मौन की संस्कृति से मुक्त करना होगा। कानून मजबूत है, पर उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए संस्थानों का नैतिक साहस। क्योंकि जब शिक्षा असुरक्षित हो जाती है, तो केवल वर्तमान नहीं, पूरा भविष्य खतरे में पड़ जाता है।

ईरान, ट्रंप और प्रतिरोध की राजनीति

जैसी करनी वैसी भरनी : साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ा होता ईरान

– डॉ. सत्यवान सौरभ

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ संघर्ष केवल सीमाओं या संसाधनों तक सीमित नहीं होते, वे विचारधाराओं, सत्ता–संतुलन और नैतिकता की भी परीक्षा लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से चला आ रहा टकराव ऐसा ही एक संघर्ष है, जो समय–समय पर नए रूपों में सामने आता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान यह टकराव जिस तीव्रता और आक्रामकता के साथ उभरा, उसने वैश्विक राजनीति को एक बार फिर शीतयुद्धोत्तर दौर की अस्थिरता की याद दिला दी। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही ईरान अमेरिका की रणनीतिक और वैचारिक राजनीति का लक्ष्य रहा है। अमेरिका ने ईरान को केवल एक राष्ट्र–राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल के रूप में देखाकृ ऐसा मॉडल जो पश्चिमी प्रभुत्व, इज़राइल–केन्द्रित पश्चिम एशिया नीति और अमेरिकी साम्राज्यवादी सोच को चुनौती देता है। यही कारण है कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव और सैन्य दबाव लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में यह नीति और अधिक कठोर, असंवेदनशील और टकरावपूर्ण हो गई। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच हुए परमाणु समझौते (श्रब्ब्।) से अमेरिका का एकतरफा हटना न केवल कूटनीतिक असंतुलन का उदाहरण था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि ट्रंप प्रशासन अंतरराष्ट्रीय सहमति और बहुपक्षीयता को किस हद तक नज़रअंदाज़ करने को तैयार था। इसके बाद ईरान पर "अधिकतम दबाव नीति" लागू की गई, जिसका उद्देश्य ईरानी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना और शासन को आंतरिक विद्रोह की ओर धकेलना था। लेकिन इतिहास साक्षी है कि दबाव हमेशा झुकाव पैदा नहीं करता। कई बार वह प्रतिरोध को जन्म देता है। ईरान के मामले में भी यही हुआ। आर्थिक कठिनाइयों, प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बावजूद ईरान ने अपने राजनीतिक अस्तित्व, संप्रभुता और वैचारिक पहचान को बनाए रखा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि ईरान का विरोध केवल अमेरिका की नीतियों से नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था से है जिसमें कुछ गिने–चुने देश स्वयं को न्यायाधीश और शेष दुनिया को अभियुक्त मान लेते हैं। "जैसी करनी वैसी भरनी" का सिद्धांत केवल नैतिक कहावत नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी गहराई से लागू होता है। पश्चिम एशिया में दशकों तक किए गए अमेरिकी हस्तक्षेपकृइराक, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरियाकृने क्षेत्र को स्थिरता नहीं, बल्कि अराजकता दी। लोकतंत्र के नाम पर सत्ता परिवर्तन, मानवाधिकारों के नाम पर सैन्य आक्रमण और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के नाम पर निर्दोष नागरिकों की हत्याकृइन सबने अमेरिका की नैतिक साख को गहरा नुकसान पहुँचाया। ऐसे में जब ईरान अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देता है, तो वह केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि उस व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है, जो ताकत को ही न्याय मानती है। ट्रंप की विदेश नीति का एक और खतरनाक पहलू उसका व्यक्तिवादी और आवेगपूर्ण स्वभाव था। कूटनीति संवाद और धैर्य से चलती है, जबकि ट्रंप की राजनीति ट्वीट, धमकी और शक्ति–प्रदर्शन पर आधारित थी।

ईरानी जनरल क़ासिम सुलेमानी की हत्या इसी मानसिकता का परिणाम थी। यह घटना न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन थी, बल्कि इसने पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। इसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब वह केवल सहने की नीति पर नहीं चल रहा। ईरान की राजनीति को अक्सर पश्चिमी मीडिया में कट्टर, दमनकारी और पिछड़ा बताकर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन यह चित्रण अधूरा और एकांगी है। ईरान की जनता ने बार–बार यह साबित किया है कि वे बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह कितनी भी आकर्षक शब्दावली में क्यों न लपेटा गया हो। ईरान में सरकार की आलोचना होती है, विरोध होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्रीय संप्रभुता की आती है, तो जनता और सत्ता एकजुट दिखाई देते हैं। यही वह तत्व है जिसे पश्चिमी रणनीतिकार अक्सर समझने में चूक जाते हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह पूरा परिदृश्य एक गंभीर चेतावनी भी है और अवसर भी। ईरान भारत का पारंपरिक मित्र रहा हैकृऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क (चाबहार बंदरगाह) और मध्य एशिया तक पहुँच के लिहाज़ से ईरान का महत्व असंदिग्ध है। लेकिन अमेरिका के दबाव में भारत का ईरान से दूरी बनाना उसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर प्रश्न खड़े करता है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को किसी तीसरे देश की नाराज़गी के डर से गिरवी न रखे। आज वैश्विक राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रही है। एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था की पकड़ ढीली पड़ रही है और बहुध्रुवीयता का उदय हो रहा है। ऐसे में ईरान जैसे देश, जो लंबे समय से दबाव और प्रतिबंधों के बीच खड़े रहे हैं, नए शक्ति–संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रूस–चीन–ईरान के बढ़ते समीकरण इस बदलाव के संकेत हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अब दुनिया केवल वाशिंगटन के इशारों पर नहीं चलेगी।

अंततः प्रश्न यह नहीं है कि ईरान सही है या अमेरिका गलत। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या वैश्विक राजनीति में शक्ति ही न्याय का एकमात्र पैमाना होगी, या फिर अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और समानता के सिद्धांतों को वास्तविक सम्मान मिलेगा। यदि बड़े राष्ट्र अपनी करनी से दुनिया को डराते रहेंगे, तो भरनी के रूप में उन्हें अस्थिरता, अविश्वास और प्रतिरोध ही मिलेगा। ईरान और ट्रंप के दौर की अमेरिकी राजनीति हमें यही सिखाती है कि दमन से स्थायित्व नहीं आता, और धमकी से सम्मान नहीं मिलता। इतिहास अंततः उसी का पक्ष लेता है जो अपनी संप्रभुता, आत्मसम्मान और जनता की चेतना के साथ खड़ा रहता है। और शायद यही "जैसी करनी वैसी भरनी" का सबसे बड़ा राजनीतिक अर्थ है।

एक भारत, श्रेष्ठ भारत का जीवंत प्रतीक है काशी–तमिल संगमम

–नरेन्द्र मोदी

कुछ दिन पहले ही मुझे सोमनाथ की पवित्र भूमि पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने का सुअवसर मिला। इस पर्व को हम वर्ष 1026 में सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई, जो इससे पहले सौराष्ट्र–तमिल संगमम के दौरान सोमनाथ आए थे और इससे पहले काशी–तमिल संगमम के समय काशी भी गए थे। ऐसे मंचों को लेकर उनकी सकारात्मक सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसलिए मैंने तय किया कि क्यों न इस विषय पर अपने कुछ विचार सांझे करूं। 'मन की बात' के एक एपिसोड के दौरान मैंने कहा था कि अपने जीवन में तमिल भाषा न सीख पाने का मुझे बहुत दुख है। यह हमारा सौभाग्य है कि बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार तमिल संस्कृति को देश में और लोकप्रिय बनाने में निरंतर जुटी हुई है। यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को और सशक्त बनाने वाला है। हमारी संस्कृति में संगम का बहुत महत्व है। इस पहलू से भी काशी–तमिल संगमम में जहां भारत की विविध परंपराओं के बीच अद्भुत सामंजस्य दिखता है, वहीं यह भी पता चलता है कि कैसे हम एक–दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम तीर्थ है। तमिलनाडु की तेनकासी को दक्षिण की काशी या दक्षिण काशी कहा जाता है। पूज्य कुमारगुरुपर स्वामी जी ने अपनी विद्वता और अध्यात्म परंपरा के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के बीच एक सशक्त और स्थायी संबंध स्थापित किया था। तमिलनाडु के महान सपूत महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को भी काशी में बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक जागरण का अद्भुत अवसर दिखा। यहीं उनका राष्ट्रवाद और प्रबल हुआ, साथ ही उनकी कविताओं को एक नई धार मिली। यहीं पर स्वतंत्र और अखंड भारत की उनकी संकल्पना को एक स्पष्ट दिशा मिली। वर्ष 2022 में वाराणसी की धरती पर काशी–तमिल संगमम की शुरुआत हुई थी। मुझे इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। तब तमिलनाडु से आए लेखकों, विद्यार्थियों, कलाकारों, विद्वानों, किसानों और अतिथियों ने काशी के साथ–साथ प्रयागराज और अयोध्या के दर्शन भी किए थे। इसके बाद के आयोजनों में इस पहल को और विस्तार दिया गया। इसका उद्देश्य यह था कि संगमम में समय–समय पर नए विषय जोड़े जाएं, नए और रचनात्मक तरीके अपनाए जाएं और इसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। वर्ष 2023 के दूसरे आयोजन में टैक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो कि भाषा इसमें बाधा न बने। इसके तीसरे संस्करण में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर विशेष फोकस रखा गया। काशी–तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसम्बर, 2025 को आरंभ हुआ। इस बार की थीम बहुत रोचक थी। तमिल करकलम् यानी तमिल सीखें। इससे काशी और दूसरी जगहों के लोगों को खूबसूरत तमिल भाषा सीखने का एक अनूठा अवसर मिला। तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने काशी के विद्याध्थियों के लिए इसे अविस्मरणीय बना दिया! प्राचीन तमिल साहित्य ग्रंथ तोलकाप्पियम का 4 भारतीय और 6 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया।

कृषि नवाचार में में पिछड़ती महिलाएं

–डॉ विजय गर्ग

देश में खेती–बागवानी में महिलाओं की भूमिका अहम है। फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक और मौसम की आहट को समझने का महिलाओं का अनुभव, ये सब मिलकर भारतीय कृषि को आगे बढ़ाता है। मगर विडंबना यह है कि जब खेती के ज्ञान–विज्ञान और नीति की बात आती है, तब महिला की मौजूदगी कमजोर पड़ जाती है। खेत में सबसे अधिक श्रम देने वाली महिला, कृषि विज्ञान और निर्णय प्रक्रिया है। यही भारतीय कृषि की सबसे गहरी और में हाशिये पर चली जाती कषि कार्यबल का बड़ा हिस्सा महिलाओं अनदेखी असमानता है। देश में का है। ग्रामीण भारत में अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ी हैं। वे फसल बोती हैं, उनकी देखरेख करती है, फसल काटती हैं, संभालती है, बीज सहेजती हैं, अनाज सुखाती हैं और खाद्य प्रसंस्करण करती हैं। इसके बावजूद उनका योगदान सिर्फ श्रम के खाते में दर्ज होता है, ज्ञान के खाते में नहीं। कृषि ऋण, बीमा, तकनीक और बाजार तक भी महिलाओं की पहुंच ख रहती है। द्य कृषि से जड़े फैसले में लिए जाते हैं। यही कारण है कि कपड़े फैसले अब भी पुरुष प्रधान ढांचों है कि कृषि विज्ञान, शोध और नवाचार के क्षेत्र अपेक्षा से बहुत कम सीमित में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षा से आश्वस्त कम दिखाई देता ह कृषि विश्वविद्यालयों में नामांकन के आंकड़े पहली नजर में करते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्तर पर छात्राओं की संख्या लगभग बराबरी पर पहुंच चुकी है। मगर यह समानता सतही है। डिग्री हासिल करने के बाद शोध संस्थानों, विस्तार सेवाओं, कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों और नीति निर्माण से जुड़े मंचों पर महिलाओं की उपस्थिति तेजी से घट जाती है। कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं उनके रास्ते रोक लेती है। 5 लेती हैं। नतीजा यह होता 1 यह होता है कि खेत में काम करने वाली महिलाओ की वास्तविक जरूरतें शोध का हिस्सा नहीं बन पातीं। उनके शरीर के अनुकूल औजार, उनके समय को समय को समझने वाली तकनीक और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने में रखने वाले नवाचार विकसित नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, ग्रामीण महिला किसान का जीवन केवल खेत तक सीमित नहीं रहता। पानी भरना, ईंधन जुटाना, भोजन पकाना, बच्चों और बुजुगों की देखभाल, पशुओं की जिम्मेदारी इन सबका भार उनकी दिनचर्या में जुड़ा रहता है। यह है। यह दोहरा बोझ उनक उनके सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों को सीमित कर कर देता है। लगातार की दर्द मुद्रा में काम करने से होने वाले स्वास्थ्य प्रभाव, थकान और समय की कमी को कृषि नीति तथा विज्ञान क बहसों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में जब विज्ञान जीवन से कट जाता है, तब उसका लाभ भी सीमित रह जाता है। ग्रामीण महिलाओं के पास पारंपरिक कृषि ज्ञान की अपार संपदा है। मौसम के संकेत, मिट्टी की प्रकृति, बीजों की गुणवत्ता, फसलों की विविधता यह सब अनुभव से अर्जित विज्ञान है। यदि इस ज्ञान को औपचारिक शिक्षा और आधुनिक शोध से जोड़ा जाए, तो कृषि नवाचार अधिक व्यावहारिक, मानवीय और टिकाऊ बन सकता है। इसलिए कृषि विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी किसी सामाजिक संवेदना का प्रश्न नहीं, बल्कि कृषि की गुणवत्ता और भविष्य से जुड़ा रणनीतिक मुद्दा है। कर्नाटक के कोलार की एक युवती इसका सशक्त उदाहरण है। छोटे किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस युवती ने फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को खेत में खड़े होकर महसूस किया। वही अनुभव उनके शोध की दिशा बना। अब वह आम उत्पादकों के लिए ऐसी तकनीक पर काम कर रही हैं, जिससे फसल नुकसान कम हो और आय बढ़े यह शोध प्रयोगशाला की कल्पना नहीं, बल्कि खेत की वास्तविक जरूरत से निकला समाधान है। ऐसे ही देश भर में और भी कई युवतियां शोध तथा खेत के बीच की दूरी कम करने के लिए प्रयासरत हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद कई युवतियां कृषि में शोध और नवाचार के कार्यों से जुड़ना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक बाधाएं उनका रास्ता रोक देती हैं। सीमित आय के कारण उच्च शिक्षा उनके लिए दूर का सपना बन जाती है। प्रवेश शुल्क, छात्रावास और पाठ्यक्रम से जुड़ी लागत उनके सामने बड़ी बाधा बन जाती है। फसल विविधता और सतत खेती के माध्यम से ग्रामीण जीवन को अधिक सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने के लिए खेती में महिलाओं के अनुभव को शोध एवं नवाचार से जोड़े जाना बेहद जरूरी है। कोटेंवा एग्रीसाइंस, दक्षिण एशिया के अध्यक्ष सुव्रत गीड के ड के अनुसार, भारत में में किसान परिवारों की अनेक बेटियों को उच्च शिक्षा इसलिए छोड़नी पड़ती है, क्योंकि शुल्क, छात्रावास और पुस्तकों का खर्च उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर होते हैं। ऐसे में मेघा– आधारित छात्रवृत्तियों का विस्तार, महिला विद्यार्थियों के लिए अवसर बढ़ाना और समुदाय आधारित प्रशिक्षण को शिक्षा से जोड़ना इस प्रतिभा शृंखला को बनाए रखने में मदद करता है जब कृषि में काम करने वाली महिलाओं को ज्ञान, कौशल और अवसर मिलते हैं, तब उसका लाभ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा कृषि समुदाय मजबूत होता है। यानी सही समय पर मिला सहयोग प्रतिभा को टूटने से बचा सकता है।

इसी संदर्भ में में कृषि क्षेत्र क्षेत्र में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का महत्त्व समझा जाना चाहिए। इनका उद्देश्य केवल शुल्क भ भरना नहीं, बल्कि छात्राओं को अवसर देना, शोध और नवाचार में उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा कृषि 1–विज्ञान में उनका नेतृत्व विकसित करना है। ऐसी पहल यह संदेश देती हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की बेटियां भी प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों और नीति मंचों तक पहुंच सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ष 2026 को श्अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया जाना इसी दिशा में वैश्विक स्वीकारोक्ति है इस घोषणा से पता चलता है कि महिलाएं केवल कृषि की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि और जलवायु अनुकूलन की वाहक भी हैं। भारत में पुरुषों के शहरा का ओर बढ़ते पलायन से खेती की जिम्मेदारी तेजी से महिलाओं पर आ रही पर इस जिम्मेदारी के साथ उन्हें अधिकार और संसाधन नहीं मिल पाए हैं। यही असंतुलन भविष्य के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि, सरकारी स्तर पर कई तरह की पहल शुरू की गई हैं, जिनमें महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना, कृषि मशीनीकरण से जुड़ी योजनाएं स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा और ग्रामीण महिला उद्यमिता कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम दिशा तो दिखाते हैं, पर इनका असर तभी होगा, जब शिक्षा और नेतृत्व को केंद्र में रखा रखा जाएगा जलवायु परिवर्तन ने कृषि की चुनौतियों को और भी गंभीर बना दिया है। सूखा, बाढ़ और अनिश्चित मौसम का सबसे गहरा असर महिला किसानों पर पड़ता है। इसलिए जलवायु अनुकूल खेती, फसल विविधता और बाजार से सीधा जुड़ाव उनके लिए विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुके हैं।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ली पार्टी प्रकोष्ठों और मोर्चों की क्लास

2027 में 2017 से भी बड़ी विजय है लक्ष्य, संपर्क, संवाद, सेवाभाव के साथ जनता के बीच करें काम–चौधरी

संवाददाता

लखनऊ। बीजेपी के राज्य मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चो, प्रकोष्ठों, विभागों के अध्यक्ष महामंत्री संयोजक और सहसंयोजको की बैठक हुई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों का प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने मार्गदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विभाग और प्रकोष्ठों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संगठन में कोई भी दायित्व छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि हर दायित्व महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ता परिश्रम, समर्पण और संगठनात्मक कौशल के बल पर पार्टी और समाज में पहचान बनाता है। समाज के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने में विभागों और प्रकोष्ठों की निर्णायक भूमिका होती है। इनके माध्यम से

सामाजिक क्षेत्रों और वर्गों में काम करने वाले लोगों को पार्टी से जोड़ा जाता है, जिससे संगठन और अधिक मजबूत होता है।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण, गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आज देश आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कानून–व्यवस्था, सुशासन, बुनियादी ढांचे के विकास और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है और यह परिवर्तन भाजपा सरकार की नीतियों और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। प्रत्येक कार्यकर्ता को संपर्क, संवाद, सेवाभाव के साथ जनता के बीच जाकर कार्य करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि हमें 2017 से भी बड़ी और ऐतिहासिक विजय के लक्ष्य के साथ अभी से जुट जाना है। संगठन ने जो दायित्व सौंपा है, उसे पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ निभाना प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। मुद्दाविहीन विपक्ष झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार के सहारे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जागरूक और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता विपक्ष के हर झूठ को तथ्यों और सच्चाई के साथ बेनकाब करेगा। पार्टी के प्रदेश महामंत्रीसंगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ता–आधारित और विचारधारा–प्रधान संगठन है। पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति उसका अनुशासित, समर्पित और प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, जो हर परिस्थिति में संगठन के लिए खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि मोर्चा, विभाग और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पार्टी और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह संगठन की योजनानुसार जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाए तथा सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाए। इससे संगठन और समाज के बीच विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

पंकज चौधरी और केशव मौर्य की मुलाकात, सियासी हल्के में चर्चा

ओबीसी वोट पाले में लाने खातिर बीजेपी में चल रहा मंथन

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों और पार्टी की रणनीतियों पर सार्थक चर्चा की। इसे शिष्टाचार भेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। पंकज चौधरी ने मुलाकात के दौरान पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा को साथ लिया। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। पंकज चौधरी ने लिखा, आज लखनऊ में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिष्टाचार भेंट की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ष्लखनऊ स्थित सरकारी आवास, सात कालिदास मार्ग पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा से शिष्टाचार भेंट की।ष्पंकज चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। इसे पार्टी संगठन और सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाने की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। पंकज चौधरी को ओबीसी चेहरा बनाए जाने का मकसद पार्टी के प्रभावी समाज कुर्मी, मौर्य और कुशवाहा पर पकड़ मजबूत करना है। राजनीतिक विश्लेषक मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार, 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। बीजेपी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल चाहती है ताकि चुनावी माहौल में कोई अंतर न रहे और पार्टी एकजुट दिखे।पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोटों में नुकसान हुआ था। समाजवादी पार्टी की पीडीए के नारे के कारण बीजेपी को ओबीसी वोटरों में सेंध का सामना करना पड़ा था।बीजेपी इस वोट बैंक को वापस जोड़ने के प्रयास में है।

लालो कृष्ण सदा सहायते ने लखनऊ में दर्ज की शानदार मौजूदगी

अभिनेता श्रुहद गोस्वामी, करण जोशी और निर्देशक अंकित सखिया ने नवाबों के शहर में बिताए यादगार पल

संवाददाता

लखनऊ। जब अतीत के बोझ से दबा एक व्यक्ति आस्था में अपना मार्गदर्शक पाता है, तब जन्म लेती है एक असाधारण कहानी। गुजराती बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता दर्ज करने के बाद लालो कृष्णा सदा सहायते अब देशभर में हिंदी दर्शकों के बीच अपनी छाप छोड़ रही है। इसी कड़ी में फिल्म के अभिनेता श्रुहद गोस्वामी, करन जोशी निर्देशक अंकित सखिया फिल्म के प्रचार के लिए नवाबों के शहर लखनऊ पहुँचे।यह फिल्म मैनिफेस्ट फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत की गई है इसके निर्माता हैं पडारिया और जय व्यास साथ ही फिल्म में कलाकार के रूप में, रीवा रच्छ, श्रुहद गोस्वामी, करण जोशी, निर्देशक अंकित सखिया मौजूद हैं. लखनऊ प्रवास के दौरान कलाकारों ने शहर की मशहूर लखनवी चाट और चाय का स्वाद लिया तथा वेव मॉल में प्रशंसकों से मुलाकात की। प्रशंसकों के उत्साह और प्रेम से अभिभूत कलाकारों ने इस अनुभव को बेहद खास बताया।'श्रुहद गोस्वामी ने कहा,"लखनऊ ने तो मेरा दिल जीत लिया हैकृयहाँ की गर्मजोशी, स्वादिष्ट चाट और अनगिनत कप चाय। वेव मॉल में हमारे प्रशंसकों से मिलना बेहद खास रहा, जिन्होंने पूरे दिल से हमारी फिल्म देखी और अपार प्रेम दिया।" 'करण जोशी ने कहा,'लखनऊ की मेहमाननवाजी बेमिसाल हैकृखाने से लेकर लोगों तक, सब कुछ अपनापन देता है। वेव मॉल में दर्शकों से मिला प्यार अविस्मरणीय है। मैं फिर यहाँ आने के लिए उत्सुक हूँ।"'निर्देशक अंकित सखिया ने कहा,'"लखनऊ ने हमें खुले दिल से अपनाया–शानदार भोजन, अद्भुत अपनापन और ढेर सारा स्नेह। वेव मॉल में दर्शकों को फिल्म से जुड़ते देखना हमारे इस सफर को और भी सार्थक बना गया।" 'लालो कृष्ण सदा सहायते' की आत्मा है लालोकृ एक साधारण पारिवारिक व्यक्ति और रिक्शा चालक, जो जीवन की कठिनाइयों और अपने अतीत की छाया से जूझ रहा है। परिस्थितियाँ उसके नियंत्रण से बाहर जाती दिखती हैं और उसका संसार भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बिखरने लगता है। तभी जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, जब उसका सामना दैवीय शक्ति से होता है।इसके बाद शुरू होती है आस्था, भय, अंतर्द्वंद्व और आशा की सशक्त यात्राकृजो उसके विश्वासों को चुनौती देती है और उसे आत्मिक रूप से परिवर्तित करती है। यथार्थ से जुड़ी और गहराई से आध्यात्मिक यह फिल्म दर्शकों को लालो के मन और आत्मा की यात्रा में सहभागी बनाती है, जहाँ खोज अंत तक जारी रहती है।

मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट, धुआं से अफरा-तफरी

सुरक्षा घेरे में बाहर निकाली गई बीएसपी चीफ

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन पर कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा होते–होते बचा। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक हॉल में शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे बिजली के बोर्ड से चिंगारियां निकलने लगीं और धुआं फैल गया। घटना उस समय हुई, जब प्रेस वार्ता समाप्त होने वाली थी। अचानक हुई घटना से हॉल में पत्रकारों, नेताओं, कार्यकर्ताओं में अफरातफरी मच गई। सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता और कार्रवाई के चलते स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया। जैसे ही बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, तेज चिंगारियों के साथ

धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ ही पलों में पूरा हॉल धुएं से भर गया जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गये। मायावती की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। सुरक्षा घेरे ने फुर्ती से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुरक्षित रूप से हॉल से बाहर निकाला और उनके आवास की ओर ले गए। त्वरित कार्रवाई के कारण किसी भी तरह की बड़ी घटना होने से बच गया। शॉर्ट सर्किट की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद सुरक्षा टीम और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की। बिना देरी किए अग्नि सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किया गया जिससे आग फैलने से पहले ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।राहत की बात कि घटना में किसी को चोट नहीं आई, कुछ देर तक कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी जरूर रही। बसपा प्रमुख की सुरक्षा को देखते तकनीकी खामी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जन्मदिन जैसे बड़े आयोजन और मीडिया की भारी मौजूदगी के बीच शॉर्ट सर्किट ने प्रशासन और आयोजकों को सतर्क कर दिया है। तकनीकी टीम सर्किट में आई खराबी की जांच कर रही है।

आबकारी विभाग तैयार कर रहा नई आबकारी नीति, प्रदेश में डिस्टिलरी प्लांट को मिलेगा बढ़ावा

– प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग को राजस्व बढ़ाने के लिए दिए थे निर्देश, विभाग नई आबकारी नीति पर कर रहा मंथन

– लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबध्द करने, शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने और आवश्यक अनुमतियों में सहूलियत देने पर विचार किया जा रहा

– नई आबकारी नीति में निर्यात पर विभिन्न सहूलियतें देने के लिए किया जा रहा मंथन

– निर्यात को आसान बनाने को नियमों में ढील देने, लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाने और अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर हो रहा विचार

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को गति देने और राजस्व संसाधनों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऐसे में आबकारी विभाग द्वारा नई आबकारी नीति 2026–27 पर मंथन किया जा रहा है। नई नीति के तहत प्रदेश में डिस्टिलरी प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सहूलियतों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

नई आबकारी नीति से निवेशकों में बढ़ेगा भरोसा

प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना आवश्यक है। इसी के तहत आबकारी विभाग को राजस्व वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में विभाग ने डिस्टिलरी प्लांट्स को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके लिए प्रदेश में नई डिस्टिलरी इकाइयों की स्थापना को सरल और आकर्षक बनाया जाएगा। लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध करने, शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने और आवश्यक अनुमतियों में सहूलियत देने पर विचार किया जा रहा है। इससे प्रदेश में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी उद्योग के क्षेत्र में एक बड़े हब के रूप में उभरेगा। बता दें कि निवेश मित्र, सिंगल विंडो सिस्टम और उद्योग अनुकूल नीतियों के जरिए प्रदेश ने रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। नई आबकारी नीति उसी श्रृंखला का हिस्सा है।

निर्यात को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही

विभाग की ओर से नई आबकारी नीति में निर्यात पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में उत्पादित स्पिरिट, अल्कोहल और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील देने, लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाने और अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर विचार चल रहा है। इससे प्रदेश के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनेंगे और विदेशी मुद्रा अर्जन में भी वृद्धि होगी। डिस्टिलरी प्लांट्स के विस्तार से आबकारी विभाग को राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही कृषि आधारित कच्चे माल की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। गन्ना, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की खपत बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिस्टिलरी उद्योग के विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के हजारों अवसर सृजित होने की संभावना है।

छावनी क्षेत्रों को नगर निगमों में मिलाने के पक्ष में नहीं यूपी सरकार

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में बताई वजह

संवाददाता

लखनऊ। राज्य सरकार कैंटोनमेंट छावनी क्षेत्रों को नगर निगमों में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। सरकार चाहती है, कैंटोनमेंट क्षेत्रों की अलग पहचान व व्यवस्था बनी रहे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय बजट के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में कहा था कि कैंटोनमेंट क्षेत्र पृथक वैधानिक व्यवस्था के तहत संचालित होते हैं और सुव्यवस्थित, स्वच्छ तथा अनुशासित क्षेत्र होते हैं। इन्हें नगर निगमों में शामिल करना अनावश्यक अव्यावहारिक तथा प्रशासनिक जटिलताओं को जन्म देगा। खन्ना ने कहा कि भारतीय रेल की काफी जमीन अनुपयोगी या उस पर अवैध कब्जा है। भूमि को जनहित में उपयोग करने की राज्यों को अनुमति नहीं है। जनहित के लिए राज्यों को उसका उपयोग करने की सरल एवं व्यावहारिकअनुमति दी जाए। प्रदेश की पुलिस इकाइयों में श्एकीकृत शस्त्र एवं गोला बारूद प्रबंधन प्रणालीश की

स्थापना करने की बात भी रखी। यूपी जैस बड़े व संवेदनशील राज्यों में पुलिस बल को प्रभावी बनाने, आधुनिकीकरण के लिए शस्त्रों व गोला बारूद के वैज्ञानिक, सुरक्षित, पारदर्शिता प्रबंधन कीआवश्यकता है।प्रदेश में सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात रखते हुए केंद्र सरकार से सहायता देने की मांग की। राज्य की आयुद्ध निर्माणी इकाइयों के सारे संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन पर्याप्त वर्क आर्डर न मिलने से इनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे रोजगार प्रभावित हो रहा है। शीघ्र नीतिगत हस्तक्षेप किया जाए ताकि उचित कार्यादेश मिल सकें।

डिप्टी सीएम ने खाई खिचड़ी, गोमती किनारे, पुराने शहर में पतंगबाजी का जमघट

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मकर संक्रांति पर लड़कियां भी पतंगों की पेच काट रही हैं। गोमती घाटों पर और पुराने शहर में पतंगबाजी का जमघट लगा हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक आयोजन में पहुंचकर खिचड़ी खाई। पार्षद अन्नू मिश्रा ने कुड़िया घाट पर पतंग उड़ाई। बच्चे छतों, गलियों और गोमती घाटों पर पतंग उड़ा रहे हैं। पतंगबाजी में कुड़िया घाट सबसे बड़ा स्पॉट है। कुड़िया घाट पर पतंगबाजी के लिए कुछ स्कूल मैनेजमेंट अपने स्टूडेंट्स को लेकर पहुंचे। यहां पहुंचे बच्चों ने बताया यह पहली बार है जब स्कूल के दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर ने शहर में कुल 9 जगहों पर सवा लाख लोगों को खिचड़ी का प्रसाद खिलाने के लिए भंडारा लगाया है। कई जगह आम लोगों ने भी खिचड़ी भोज का आयोजन किया है। हजरतगंज में पुलिसवालों ने जरूरतमंदों को मिठाई खिलाकर उनको कंबल बांटे। केजीएमयू में सरस्वती मंदिर गार्डन में मेडिकल स्टूडेंट्स ने पतंग उड़ाई और पेच लड़ाए। कैंपस में रह रहकर वो काटा की आवाजें गूंजती रहीं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सरोजनीनगर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जनहित व्यापार मंडल की एयरपोर्ट शाखा ने खिचड़ी प्रसाद वितरण किया। यह आयोजन अमौसी एयरपोर्ट तिराहा पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में राहगीरों, स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक खिचड़ी और रायते का प्रसाद ग्रहण किया। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे सामाजिक एकता का प्रतीक बताया।

कृष्णानगर से 13 वर्षीय बच्ची लापता, मां ने थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के कृष्णानगर क्षेत्र से 13 वर्षीय बच्ची नैन्सी लापता हो गई है। उसकी मां गोमती ने कृष्णानगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। हरि ओम नगर, गली नंबर 01 की निवासी गोमती ने बताया कि उनकी बेटी नैन्सी दोपहर करीब 2 बजे घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। गोमती एक निजी नौकरी करती हैं और घटना के दिन सुबह काम पर गई थीं, उस समय उनके तीनों बच्चे घर पर थे। जब गोमती शाम को घर लौटीं, तो नैन्सी वहां नहीं थी। उन्होंने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कृष्णानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बच्ची का हुलिया भी बताया गया है। नैन्सी का रंग सांवला है, कद लगभग 4.5 फीट है। उसने लाल स्वेटर और शाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही पैरों में जूते भी हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्ची की तलाश की जा रही है।

संक्षिप्त

राजधानी में मौसम साफ, चल रही ठंडी हवा, अगले 5 दिन में ठंड से मिलेगी राहत

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से मौसम साफ है। हल्की धुंध के बाद समय से धूप निकल आई। हालांकि, ठंडी हवा चलने से गलन महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिन में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ेगा जिससे ठंड से कुछ राहत मिलेगी। आज अधिकतम 21 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रह सकता है। एक दिन पहले बुधवार को लखनऊ में मौसम साफ रहा। सुबह से चटक धूप निकली, लेकिन सुबह और शाम के समय गलन के साथ में ठंड का असर बना रहा। अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। लखनऊ में आज मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन 16 जनवरी को मौसम विभाग की तरफ से कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 5–6 दिनों के दौरान 4–6 डिग्री की बढ़त रहने की संभावना है।

फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का समान जला, फायर की तीन गाड़ियों ने आग बुझाई

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के कल्याणपुर रिंग रोड क्षेत्र में बुधवार देर रात एक फर्नीचर की गोदाम में आग लग गई। घटना की सूचना रात करीब 12.57 बजे फायर स्टेशन इंदिरा नगर को मिली। आग मारुति शोरूम के सामने स्थित फर्नीचर गोदाम में लगी थी। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी इंदिरा नगर तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचने पर देखा गया कि भवन के ग्राउंड फ्लोट पर आग भड़क रही थी। गोदाम का शटर खुला हुआ था। आग इतनी तेज थी दूर तक उसकी लपटे आ रही थी। पूरे इलाके में धुआं भर गया था। फायर कर्मियों ने तत्काल हौज पाइप और होज–रील से आग बुझाना शुरू किया गया। आग को देखते हुए अतिरिक्त सहायता के लिए दूसरे फायर स्टेशन से फायर टेंडर मंगाए गए। कुछ ही समय में फायर स्टेशन बीकेटी की यूनिट भी मौके पर पहुंच गई।

क्या यूपी सरकार मौत का इंतजार कर रही है : संजय सिंह

आप सांसद संजय सिंह ने उदयगंज और सचिवालय कॉलोनी का दौरा किया

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में महीनों से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर जनता का दर्द अब सड़कों तक पहुंचता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को उदयगंज और सचिवालय कॉलोनी का दौरा कर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा राजधानी के वीआईपी इलाकों में आठ महीने से दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन आंख मूंदे बैठे हैं। संजय सिंह लखनऊ के उदयगंज इलाके में पहुंचे और स्थानीय लोगों से सीधे मुलाकात कर गंदे पानी से जुड़ी समस्याएं सुनीं। लोगों ने बताया कि नलों से मटमैला, बदबूदार और गंदगी से भरा पानी आ रहा है। इस पानी को पीने से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लगातार बीमार हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई परिवारों को पीने के पानी के लिए दूर–दूर भटकना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। आप सांसद ने कहा सचिवालय कॉलोनी और उदयगंज जैसे इलाके राजधानी के बीचों–बीच हैं, जहां बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहते हैं। अगर यहां लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, तो प्रदेश के गांवों और कस्बों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नलों से आ रहा पानी इतना गंदा है कि उसमें बदबू, कीचड़ और गंदगी साफ नजर आती है, जिससे डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, बुखार और त्वचा रोग तेजी से फैल रहे हैं।संजय सिंह ने कहा स्थानीय लोग महीनों से जलकल विभाग, नगर निगम और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। लिखित शिकायतें दी गईं, अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। न तो पाइपलाइन बदली गई, न पानी की टंकियों की सफाई हुई और न ही नई बोरिंग कराई गई। उन्होंने इसे जनता की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ बताया। आप सांसद ने इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार लखनऊ में भी ऐसी ही किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है? क्या तब ही प्रशासन जागेगा, जब लोगों की जान चली जाएगी? उन्होंने साफ कहा कि साफ पानी देना सरकार का फर्ज है, कोई एहसान नहीं। संजय सिंह ने कहा सरकार जल जीवन मिशन और स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि राजधानी में ही लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यह भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का जीता–जागता उदाहरण है। अगर पैसा सही तरीके से खर्च हुआ होता, तो आज लखनऊ की जनता इस हालत में नहीं होती। उन्होंने मांग की कि सचिवालय कॉलोनी और उदयगंज में तुरंत नई बोरिंग कराई जाए, दूषित पाइपलाइनों को बदला जाए और स्थायी समाधान होने तक टैंकरों से शुद्ध पानी की आपूर्ति की जाए। साथ ही गंदा पानी सप्लाई कराने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ थ्प् दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।

खिचड़ी महापर्व : गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

बाबा का खप्पर भरने को श्रध्दा की अंजुरी में आस्था की खिचड़ी लेकर उमड़े लाखों श्रध्दालु
सबसे पहले सीएम योगी ने महायोगी गोरखनाथ जी को चढ़ाई आस्था की पवित्र खिचड़ी
मकर संक्रांति पर श्रीनाथ जी का विधिविधान से पूजन कर गोरक्षपीठाधीश्वर ने की प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की कामना
सभी व्यवस्थाओं पर खुद नजर बनाए रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

बीएनई

गोरखपुर। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ को नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई और लोकमंगल की कामना की। सीएम

योगी के बाद नाथ योगियों, साधु संतों ने भी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ मंदिर के गर्भगृह कपाट को आमजन के लिए खोल दिया गया। खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर में आस्था का सैलाब नजर आया। गोरखनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु महायोगी गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए पहुंचे। लोक मान्यता के अनुसार त्रेतायुग से बाबा गोरखनाथ का खप्पर भरने की परंपरा का अनुसरण करते हुए श्रद्धा की अंजुरी में आस्था की खिचड़ी लेकर श्रद्धालु नतमस्तक रहे। महायोगी गोरखनाथ को नेपाल राजपरिवार की तरफ से भेजी गई खिचड़ी भी श्रद्धापूर्वक अर्पित की गई। खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में लगे विशाल मेले का भ्रमण कर आनंद उठाया। मनोरंजन के साथ जरूरी वस्तुओं की जमकर खरीदारी की।

मकर संक्रांति पर गुरुवार को भोर में गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नाथपंथ की परंपरा के अनुसार गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में जमीन पर बैठ कर, सीटी बजाकर गुरु गोरखनाथ को प्रणाम कर आदेश लिया। फिर विधिविधान से पूजन कर गोरक्षपीठ की ओर से श्रीनाथ जी को खिचड़ी (चावल, दाल, तिल, सब्जी, हल्दी, नमक आदि) चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने मुख्य मंदिर में स्थापित अन्य देव विग्रहों की पूजा की। फिर योगिराज बाबा गंभीरनाथ, अपने दादागुरु महंत दिग्विजयनाथ, गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ, नौमीनाथ व अन्य नाथ योगियों की प्रतिमाओं समक्ष शीश नवाकर खिचड़ी भोग अर्पित किया। सीएम योगी द्वारा बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भोग अर्पित करने के बाद सुख समृद्धि की मंगलकामना लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत अन्य राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने भी कतारबद्ध होकर महायोगी गोरखनाथ को श्रद्धा की खिचड़ी चढ़ाई।

लगातार चलता रहा खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला

महायोगी गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला लगातार चलता रहा। पूरे दिन भक्तों की कतार नहीं टूटी। दोपहर बाद तक गोरखनाथ मंदिर आने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं का रेला दिख रहा था। खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में स्थित सभी देवी देवताओं के विग्रहों का पूजन कर ब्रह्मलीन महंत बाबा गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद भी लिया। पूरा दिन मंदिर परिसर गुरु गोरखनाथ की जय जयकार से गूंजता रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर मंदिर व जिला प्रशासन की ओर से समुचित प्रबंध किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए थे।

भोर में तीन बजे ही लग गई थी लंबी कतार

गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला लोक श्रद्धाभाव के साथ सामाजिक समरसता का भी मेला है। हर वर्ग के लोग नंगे पांव कतारबद्ध होकर बारी बारी भगवान गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे थे। कोई मुठ्ठी भर श्रद्धा का चावल लेकर आ रहा था तो कोई झोली भर। पर, महायोगी के प्रति भाव सभी का एक समान था। न जाति का बंधन था, न धर्म का। बुधवार को भी लाखों श्रद्धालुओं ने खिचड़ी चढ़ाई थी। गुरुवार को यह संख्या और बढ़ गई। भोर में तीन बजे ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार मंदिर परिसर से बाहर सड़क तक लग गई थी। अलग–अलग गेट और बैरिकेडिंग से श्रद्धालुओं की भीड़ को संभाला जा रहा था।

मंदिर में हुआ खिचड़ी सहभोज का आयोजन

मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धा के साथ सभी श्रद्धालुओं को खिचड़ी का प्रसाद वितरित करने के लिए सहभोज का आयोजन किया गया। अमीर–गरीब, जाति, वर्ग का भेदभाव भुलाकर सबने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में आमंत्रित अतिथियों के लिए भी सहभोज का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों, उद्यमियों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं गण्यमान्य लोगों की सहभागिता रही।

नेपाल में राजगुरु माने जाते हैं महायोगी गोरखनाथ : डॉ. प्रदीप राव

नाथपंथ के अध्येता डॉ. प्रदीप कुमार राव बताते हैं कि महायोगी गुरु गोरखनाथ का नेपाल से भी गहरा संबंध है। मकर संक्रांति पर गुरु गोरखनाथ को गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा खिचड़ी चढ़ाए जाने के बाद नेपाल राजपरिवार की तरफ से आई खिचड़ी चढ़ाई जाती है। गुरु गोरखनाथ जी नेपाल के राजगुरु माने जाते हैं।

त्रेतायुगीन मानी जाती है गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा

गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेतायुगीन मानी जाती है। मान्यता है कि तत्समय आदियोगी गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। मां ने उनके भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने मां ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुर आ पहुंचे और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धूनी रमाकर साधनालीन हो गए। उनका तेज देख लोग उनके खप्पर में अन्न (चावल, दाल आदि) दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति पर अहर्निश जारी है। कहा जाता है कि उधर मां ज्वाला देवी के दरबार में बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है।

असम के मुख्यमंत्री ने एसजेवीएन के 70 मेगावाट धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया

बीएनई

शिमला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) की 70 मेगावाट धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन असम के विद्युत मंत्री प्रशांत फुकन, एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भूपेंद्र गुप्ता, एपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक, डॉ. कृष्ण कुमार द्विवेदी, आईएएस, एसीएस(ऊर्जा)और एपीडीसीएल के अध्यक्ष, राकेश कुमार, भा.प्रशा.सेवा, एसजेवीएन के निदेशक(कार्मिक), अजय कुमार शर्मा और असम सरकार एवं एसजेवीएन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया। इस अवसर पर, भूपेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय विद्युत मंत्री, मनोहर लाल और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रल्हाद जोशी, भारत सरकार और असम सरकार का परियोजना को निष्पादित करने में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए तथा राज्य में निष्पादनाधीन और आगामी अन्य परियोजनाओं के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना का निर्माण पूर्ण होने से क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने और ऊर्जा सुरक्षा एवं स्थायित्व के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता सिद्ध होती है। अजय कुमार शर्मा ने कहा कि धुबरी सौर ऊर्जा परियोजना, विकास एवं प्रचालन दोनों चरणों में स्थानीय समुदायों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार उत्पन्न करने के साथ–साथ, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा की आपूर्ति करके असम के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करेगा। एसजीईएल द्वारा 70 मेगावाट धुबरी

सौर ऊर्जा परियोजना को असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई 330 एकड़ भूमि पर 28 वर्ष की लीज़ के आधार पर गाँव खुदीगाँव पीटी–II, बिलासीपारा रेवेन्यू सर्कल, ज़िला धुबरी, असम में विकसित किया गया है। यह परियोजना एपीडीसीएल ने दिनांक 16 फरवरी 2023 को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एसजीईएल को रुपए 3.92 प्रति यूनिट के टैरिफ पर अवार्ड की गई थी। परियोजना की ईपीसी लागत रुपए 367.44 करोड़ है। यह परियोजना 25 वर्षों में लगभग 3,230 मि.यू. अनुमानित संचित विद्युत उत्पादन के साथ प्रथम वर्ष में 23% के क्षमता उपयोग फैक्टर (सीयूएफ) पर 141.13 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन के लिए डिज़ाइन की गई है। इस परियोजना से लगभग 1,58,270 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना है। यह परियोजना असम राज्य की प्रथम बड़े पैमाने की सौर परियोजना है और साथ ही एसजेवीएन की उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में प्रथम प्रचालनरत परियोजना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूप से दिनांक 04 मार्च 2024 को इस परियोजना की वर्चुअली आधारशिला रखी थी।

निटको लिमिटेड ने बिक्री में 85 प्रतिशत की मज़बूत वृध्दि दर्ज की

बीएनई

देहरादून। टाइल्स, मार्बल और मोज़ेक इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी निटको लिमिटेड ने जनवरी 2025 की तुलना में दिसंबर 2025 के दौरान बिक्री में 85 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की है। बिक्री में यह वृद्धि दिखाती है कि बिज़नेस मोमेंटम मज़बूत है और कंपनी की सभी उत्पाद श्रेणियों में निरंतर मांग बनी हुई है। यह वृद्धि ध्यान पूर्वक किए गए अमल, बाजार में मज़बूत मौजूदगी और ग्राहकों के भरोसे की वजह से हुई, जो स्केलेबल और टिकाऊ वृद्धि की दिशा में निटको की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मांग मज़बूत होने से, लगातार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सुधार, बेहतर वितरण नेटवर्क और परिचालन में दक्षता के चलते बिक्री में तेज़ी को सपोर्ट मिला है। इस प्रदर्शन पर निटको लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, विवेक तलवार ने कहा, ''सेल्स में 85 प्रतिशत की वृद्धि हमारी कारोबारी रणनीति की ताकत, हमारी टीमों की लगन और हमारे ग्राहकों के भरोसे को दिखाती है। हम सतत वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किए हुए हैं और साथ ही इनोवेशन, क्षमता विस्तार और ग्राहक अनुभव में निवेश करना जारी रखेंगे।'' कंपनी ने बताया कि बिक्री में यह वृद्धि उनके मुख्य उत्पादों और सर्विस लाइन में मज़बूत परफॉर्मेंस, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स रीच, रणनीतिक साझेदारी और बाजार के अच्छे हालात की वजह से हुई है। अब आगे की ओर निटको लिमिटेड अपनी वृद्धि की संभावनाओं को लेकर आशावादी है। कंपनी ने अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, निरंतर इनोवेशन और ग्राहकों व स्टेकहोल्डर्स दोनों को वैल्यू देने पर लगातार ध्यान देकर अपनी मार्केट पोजीशन को मज़बूत करते रहने की योजना बनाई है।

बुजुर्गों के लिए बनेगा वृद्ध आश्रम, भोजन से भरी होगी थाली

घर से उपेक्षित और तिरस्कृत बुजुर्गों के लिए अनूठी सामाजिक पहल
समाजसेवी पंडित भोलानाथ शुक्ल ने मकर संक्रांति पर की मुफ्त लंगर की शुरुआत

बीएनई

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी एक सकारात्मक खबर आई है। गुरुवार को मकर संक्रांति पर्व पर जनपद के प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी पंडित भोलानाथ शुक्ल की तरफ से वृद्ध आश्रम संचालित करने और बुजुर्गों को मुफ्त लंगर की शुरुवात की गई। मकर संक्रांति के अवसर पर भोलानाथ शुक्ल ने अपने पैतृक गांव हरीपुर में बाबा के तालाब पर स्थित माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ पर बुजुर्गों के लिए मुफ्त में भोजन की सुविधा की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि यह लंगर ठंड में सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर ठंड में शाम 6:00 बजे शाम तक चलेगा। जबकि गर्मी के दिनों में यह सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर रात 9:00 बजे तक जारी रहेगा। भोलानाथ शुक्ल की तरफ से की गई यह पहल पूरे जनपद के लिए सराहनीय और गौरव का विषय है। उन्होंने कहा फिलहाल अभी वृद्धो के लिए रहने की नहीं सिर्फ भोजन की व्यवस्था है। वृद्ध आश्रम का शिन्यास हम 26 जनवरी को करेंगे। लंगर में दोनों वक्त कोई भी वृद्ध और असहाय व्यक्ति जाकर भोजन कर सकता है। उन्होंने कहा हमने संकल्प लिया है कि हर महीने 5,00000 बुजुर्गों की सेवा पर खर्च करेंगे। उन्होंने बातचीत में बताया कि समाज में बुजुर्ग तिरस्कृत हो रहे हैं। जिसकी वजह से मेरे मन में ख्याल आया और मैं वृद्ध आश्रम खोलकर बुकुर्गो की सेवा करूँ क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है।

संक्षिप्त

सचिन-अंजलि और सारा तेंदुलकर ने भी किया मतदान, बोले- यह चुनाव महत्वपूर्ण, लोगों से की यह अपील

एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। इसी बीच मुंबई में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपने मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी ने मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया को अपना इंक लगा हुआ अंगूठा दिखाया और लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर संदेश भी दिया। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, सचिन का संदेश मतदान के बाद सचिन तेंदुलकर ने चुनाव की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, श्यह

बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे हमें अवसर मिलता है कि हम अपने वोट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कर सकें। सभी से अपील है कि घर से बाहर निकलें और वोट डालें। सचिन ने लोगों को जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया और मतदान को लोकतांत्रिक अधिकार के साथ कर्तव्य भी बताया। मुंबई में उत्साह के साथ मतदान मुंबई के अलग–अलग वार्डों में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया जारी है। कई जगह युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। बीएमसी चुनाव हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ राजधानी मुंबई के प्रशासन के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं।

'पुनर्वास से पुनर्जीवन' की बड़ी सफलता, 81 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता

बंदूक के नहीं, विकास के साथ है भविष्य - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान को एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। 'पूना मारगेम' के अंतर्गत साउथ सब ज़ोनल ब्यूरो से जुड़े 52 माओवादी कैडरों ने हिंसा और हथियारों का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा विकास की मुख्यधारा को अपनाया है। इन पर कुल 1.41 करोड़ का इनाम घोषित था, जिससे यह आत्मसमर्पण अभियान अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धियों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे हिंसा की विचारधारा पर विश्वास की निर्णायक विजय बताया और कहा कि पिछले 48 घंटों में कुल 81 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि माओवाद अब केवल कमजोर नहीं पड़ रहा, बल्कि पूरी तरह बिखर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में अब माओवादी संगठन के साथ–साथ उसकी विकृत विचारधारा और उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम भी ध्वस्त हो चुका है। जहाँ कभी भय, भ्रम और दबाव का माहौल था, वहाँ अब शासन की सशक्त उपस्थिति, सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास योजनाओं की प्रभावी पहुँच ने लोगों में भरोसा पैदा किया है। 'पुनर्वास से पुनर्जीवन' अभियान के तहत सरकार उन सभी भटके युवाओं को सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और आजीविका के अवसर उपलब्ध करा रही है, जो हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, और यह व्यापक आत्मसमर्पण उसी भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन को इस सफलता का आधार बताते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल–मुक्त भारत का संकल्प अब तेजी से निर्णायक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि छत्तीसगढ़ में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब भय की जगह भविष्य आकार ले रहा है, जहाँ सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएँ, आजीविका और शासन की पहुँच लगातार मजबूत हो रही है।

पंजाब नैशनल बैंक द्वारा विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह तथा कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन

बीएनई

देहरादून। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत के अग्रणी बैंकों में से एक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा अपने प्रधान कार्यालय में विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह तथा कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में बैंक के कार्यपालक निदेशक बी. पी. महापात्र, अमित कुमार श्रीवास्तव और मुख्य सतर्कता अधिकारी, राघवेंद्र कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक, सुमेश कुमार द्वारा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन और प्रख्यात कवियों चिराग जैन और अरूण जैमिनी तथा धर्मवीर, उपनिदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वागत के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्र और बैंक के शीर्ष कार्यपालकों के

कर–कमलों से बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन से संबन्धित "वार्षिक कैलेंडर, बैंक की तिमाही पत्रिका पीएनबी प्रतिभा–कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा सुरक्षा विशेषांक और मनोज कुमार श्रीवास्तव, महाप्रबंधक द्वारा लिखी गई पुस्तक "केंचुली" का विमोचन भी किया गया। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि "हिंदी देश की राजभाषा है और इसके प्रचार–प्रसार एवं कार्यान्वयन हेतु पंजाब नैशनल बैंक दृढ़ संकल्पित है। जब हम विकसीत भारत–2047 की संकल्पना कर रहे हैं उसमे भाषा का महत्व बहुत अधिक हैं। अगर हमें देश के कोने–कोने तक पहुचना हैं , बैंक के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को यदि हम बैंकिंग सेवाएं देना चाहते हैं तो उसका एकमात्र माध्यम हिन्दी और केवल हिन्दी है। हम हिन्दी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हुए हिन्दी का प्रचार–प्रसार कर रहे हैं। विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं सबकी अपनी राष्ट्रीय भाषा है और हमारे देश में हिन्दी ही इतनी सशक्त भाषा है जिसके अंदर देश को एकसूत्र में पिरोने की क्षमता है। पंजाब नैशनल बैंक अपने डिजिटल उत्पादों में हिंदी व 13 क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से अपना कारोबार बढ़ा रहा है और राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। यह स्वतन्त्रता सेनानी स्व. लाला लाजपत रॉय द्वारा स्थापित किया हुआ प्रथम स्वदेशी बैंक है। अतः देश की भाषा को जन–जन की भाषा बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर सबसे अधिक हैं। कवि सम्मेलन हेतु आए दोनों प्रख्यात कवियों ने अपनी हास्य और व्यंगात्मक कविताओं से इस कार्यक्रम और भी यादगार बनाया। इस अवसर पर हिंदी में मुख्य रूप से अधिक कार्य करने वाले उच्च अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय एवं कार्यपालक निदेशकों द्वारा शील्ड व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन मनीषा शर्मा, विभागीय प्रमुख द्वारा पंजाब नैशनल बैंक में किए जा रहे राजभाषा कार्यान्वयन से संबन्धित कार्यों की एक प्रस्तुति और आशीष शर्मा, मुख्य प्रबन्धक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर, विश्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया

एजेंसी

नई दिल्ली। विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर सकारात्मक आकलन पेश किया है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने 2025–26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। यह उसके जून के अनुमान से 0.9 प्रतिशत अधिक है। घरेलू मांग के चलते मजबूत वृद्धि विश्व बैंक ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में यह भी कहा है कि वर्ष 2026–27 में भारत की वृद्धि दर धीमी होकर 6.5 प्रतिशत रह सकती है। यह अनुमान इस धारणा पर आधारित है कि अमेरिका का 50 प्रतिशत आयात शुल्क इस दौरान लागू रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है, इसके बावजूद भारत से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर बनाए रखने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने कहा कि अमेरिका को होने वाले कुछ निर्यातों पर उच्च शुल्क के बावजूद वृद्धि के पूर्वानुमान में जून के अनुमानों के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी मुख्य वजह यह है कि उन शुल्कों के प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई घरेलू मांग में मजबूत वृद्धि और अधिक निर्यात द्वारा की गई। भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत है। 2025–26 में वृद्धि दर बढ़कर 7.2 प्रतिशत होने का अनुमान रिपोर्ट में कहा गया, वित्त वर्ष 2027–28 में वृद्धि दर बढ़कर 6.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिसे मजबूत सेवा गतिविधियों के साथ ही निर्यात में सुधार और निवेश में तेजी से समर्थन मिलेगा। चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि पर रिपोर्ट में कहा गया, भारत में वित्त वर्ष 2025–26 में वृद्धि दर बढ़कर 7.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743